

# अब झारखंड भी कांग्रेस के हाथ से निकलेगा, बिहार के चुनाव के कारण

झारखंड के मु.मंत्री हेमंत सोरेन तीन दिन से दिल्ली में हैं तथा गृह मंत्री अमित शाह से सम्पर्क में हैं। चर्चा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब इंडिया गठबंधन छोड़कर, भाजपा से हाथ मिलाएगा

## नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

जयपुर, 2 दिसंबर। पाँचसो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कुलदीप कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि चिकित्सीय साक्ष्य और पीड़िता के बयानों से साबित है कि अभियुक्त ने उसके साथ संबंध बनाए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष

# एसआईआर के खिलाफ संयुक्त प्रदर्शन से कतराए कुछ विपक्षी दल

तृणमूल कांग्रेस, जेएमएम और सपा, कांग्रेस के साथ खड़े नज़र आना नहीं चाहते

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। संयुक्त विपक्ष, जिसने वंदे मातरम् विवाद और एसआईआर पर संसद में चर्चा करवाने के लिए मोदी सरकार पर दबाव बनाने में सफलता पाई थी, में अब दरार साफ दिखाई दे रही है। 'इंडिया' गठबंधन के बनने के बाद पहली बार विपक्ष इस बात पर बंटा हुआ दिख रहा है कि एसआईआर के खिलाफ संयुक्त प्रदर्शन किया जाए या नहीं—और यह दरार अब तक दिखाई पड़ी उनकी संयुक्त राजनीतिक चुनौती को कमजोर कर सकती है।

वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, समाजवादी पार्टी (सपा) इस समय कांग्रेस के साथ बहुत नज़दीक दिखने को लेकर बहुत ज्यादा सावधान है। हाल ही में बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली हार—जिसमें कांग्रेस एक प्रमुख सहयोगी थी—ने सपा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कांग्रेस से निकटता कहीं चुनावी जोखिम न बढ़ा दे। सपा के अंदरूनी लोग मानते हैं कि

■ सपा के आंतरिक सूत्रों ने बताया कि पार्टी कांग्रेस के साथ तालमेल पर दोबारा सोच रही है और इसलिए वह कांग्रेस के ज्यादा निकट नज़र आने से कतरा रही है।

■ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल पहले ही कांग्रेस नेतृत्व वाली सामूहिक रणनीति से दूरी बना चुकी है। अरविंद केजरीवाल पहले ही इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हैं।

■ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार के रवैये के कारण कांग्रेस से नाराज़ है।

■ देखना यह है कि क्या विपक्ष का गतिरोध एसआईआर व वंदे मातरम् मुद्दे पर विपक्ष के सामूहिक विरोध की हवा निकाल देगा?

विधानसभा में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।

इस तनाव को और बढ़ाते हुए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कांग्रेस से नाराज़ बताए जा रहे हैं, क्योंकि हाल की राजनीतिक बैठकों में उनकी पार्टी जेएमएम को किनारे कर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-रेणु मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य सरकार निकल सकती है।

कांग्रेस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के साथ गठबंधन सरकार चला रही है, जिसका नेतृत्व हेमंत सोरेन कर रहे हैं।

विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि हेमंत सोरेन पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हैं और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हैं, जिसे साझेदार बदलने की उनकी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। सोरेन की नाराज़गी और दुख की वजह बिहार में उनके प्रति कांग्रेस का व्यवहार है। बिहार में 30 से ज्यादा सीटों पर आदिवासी वोटों का असर है और जब जेएमएम ने 6 सीटों की मांग की, तो

■ हेमंत सोरेन की नाराज़गी की शुरुआत हुई, जब उन्होंने कांग्रेस से बिहार की तीस ट्राइबल सीटों में से छः सीटों पर टिकट मांगा। पर, कांग्रेस ने यह कह कर बात टाल दी की आरजेडी बिहार में इंडिया गठबंधन की वरिष्ठ पार्टनर है। अतः आरजेडी ही निर्णय लेगी, सीटों के बंटवारे के बारे में।

■ हेमंत सोरेन ने जवाबी तर्क दिया कि कांग्रेस उसकी 35 ट्राइबल सीटों में से 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे दे और फिर वे सभी 36 ट्राइबल सीटों पर जमकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे।

■ पर, ये दो सीटें भी सोरेन को नहीं मिलीं तो क्रोधित सोरेन ने राहुल गांधी के विशेष चहेते, बिहार के प्रभारी अलुवीरा को बहुत अपशब्द सुनाये और इंडिया गठबंधन छोड़ने का निर्णय लिया।

■ 42 सदस्यी विधानसभा में कांग्रेस के 16 विधायक हैं तथा आरजेडी के चार, अतः हेमंत सोरेन का आकलन है कि अगर इंडिया गठबंधन के 20 विधायक चले भी जाते हैं तो भाजपा के 21 विधायक उनके समर्थन में आ जाएंगे और सरकार चलती रहेगी।

कांग्रेस ने कह दिया कि आरजेडी वरिष्ठ साझेदार है और वही सीटें तय करेगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# एक अन्य कांग्रेस प्रभारी राजस्थान ट्राइबल इलाके का कुण्डा करने में लगे हैं

मेवाड़ की सात सीटों (उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बाँसवाड़ा, राजसमंद, सलूबर व प्रतापगढ़) में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्तियाँ चौंकाने वाली हैं

-रेणु मिश्र-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। राहुल गांधी लगातार ओबीसी समुदाय की बात करते हैं और कहते हैं कि उनकी जनसंख्या के अनुसार उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन राहुल को उनके प्रिय "संगठन सृजन अभियान" में पूरी तरह गुमराह किया गया है, और ऐसा लगता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि यह सब कैसे, कब और कहाँ हुआ।

मेवाड़-उदयपुर जिले में एआईसीसी के प्रभारी रंधावा, सीपी जोशी से सलाह-मशविरा करके काम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ तीन जिलाध्यक्ष (उदयपुर ग्रामीण, डूंगरपुर व बाँसवाड़ा) ही ट्राइबल हैं।

■ दो जिलाध्यक्ष (उदयपुर सिटी व चित्तौड़गढ़) राजपूत हैं।

■ प्रतापगढ़ में भी दो परस्पर विरोधी राजपूत ग्रुप्स की प्रतिस्पर्धा में नियुक्ति पेंडिंग है।

■ राहुल गांधी बार-बार कह रहे हैं, ओबीसी जनता को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, उनकी जनसंख्या के अनुरूप। अतः राहुल ये सामाजिक संतुलन बिठाने पर बहुत जोर दे रहे हैं तथा विशेषकर, मेवाड़ में सबसे अधिक जनसंख्या ट्राइबल्स की है तथा दूसरे नम्बर पर हैं ओबीसी।

## प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम 'सेवा तीर्थ'

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। केन्द्र सरकार ने एक अहम फैसले में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) वाले नए परिसर का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया। सेन्ट्रल विस्था प्रोजेक्ट के तहत निर्मित यह परिसर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नया

■ सभी राज्यों के राजभवन अब लोक भवन कहलायेंगे।

कार्यालय होगा। पहले इस जगह को एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव नाम दिया गया था।

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि सेवा तीर्थ को एक ऐसा कार्यस्थल बनाया जा रहा है, जहाँ सेवा भावना ही सर्वोपरि होगी और राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिकताएं आकार लेंगी। सेवा, कर्तव्य और पारदर्शिता को शासन का आधार बनाने के प्रयासों के तहत, राज्यों में राज्यपालों के आवास के नाम राजभवन से बदलकर लोकभवन करने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# सेना ने इमरान की बहनों को इमरान से मिलने दिया

इमरान को स्वस्थ व खुश देखकर, सस्पेंस तो खत्म हुआ, पर, सेना अभी असमंजस की स्थिति में है इमरान के बारे में

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो अगस्त 2023 से जेल में हैं, को आखिरकार एक बड़ी राहत मिली, जब जेल प्रशासन ने आखिरकार उनकी बहनों को उनसे मिलने की अनुमति दे दी। इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पी.टी.आई.) ने इमरान खान से मिलने की मांग को लेकर देशभर में लगातार जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए।

जेल अधिकारियों की अनुमति मिलने के बाद उनकी बहनों ने इमरान खान से मुलाकात की और बताया कि पूर्व क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री पूरी तरह ठीक हैं।

इस बीच, पड़ोसी देश भारत में इमरान की सेहत को लेकर चिंता इस

■ इमरान पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, सेना की इच्छा व मदद से। पर, शीघ्र ही मतभेद उत्पन्न हो गए, दोनों के बीच और इमरान को अपना पद छोड़ना पड़ा।

■ इमरान के सेना के साथ संबंध कभी नरम, कभी गरम चलते रहे।

■ पर, अब सेना, शाहबाज़ शरीफ से भी ज्यादा खुश नहीं है। अतः मिश्रित भावनाओं के बीच इमरान राजनीति के सैन्ट्रल स्टेज पर आ गए हैं, 23 अगस्त से लगातार जेल में कैद होने के कारण।

■ क्या सेना कुछ नरम हुई है, इमरान के प्रति। अतः, एक बार और प्र.मंत्री बन सकते हैं, इमरान, अगर मधुर संबंध चलते रहे, सेना व इमरान के बीच। नहीं तो कई नाटक देखने पड़ेंगे, पाकिस्तान के राजनीतिक मंच पर।

प्रकार बढ़ रही थी, मानो कोई बड़ा राजनीतिक संकेत पैदा हो गया हो।

राजनेता और मीडिया लगातार इमरान की सेहत और उनको होने वाले खतरों

के बारे में बेचैनी से लिख रहे थे। इस मुद्दे को लेकर भारत में सोशल मीडिया का माहौल गर्मा गया था। एक वर्ग इमरान की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, जबकि दूसरा कह रहा था कि इमरान एक कट्टरपंथी मुस्लिम है और कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों पर गंभीर हमलों में उनकी भूमिका रही थी।

सोशल मीडिया पर कई लोग यह भी कह रहे हैं कि इमरान के लिए दुःख जताने के बजाय, भारत को उन बड़े वैश्विक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जो भारत की सुरक्षा और हितों से जुड़े हैं।

फिर भी, इमरान खान भारत में खास रुचि का विषय बने रहते हैं। इसका एक बड़ा कारण उनका शासन क्लिकेट करियर है, जिसने उन्हें भारत में भी लोकप्रिय बनाया।

लेकिन, अपने क्रिकेट के दिनों से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## इंडिया गठबंधन की नई रणनीति बनाने के लिये बैठक आज

नयी दिल्ली, 02 दिसम्बर। लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने को लेकर मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में सरकार तथा विपक्षी दलों के बीच बनी सहमति के बाद, अब विपक्षी इंडिया गठबंधन ने संसद में

■ सरकार और विपक्ष में संसद चलाने पर हुई सहमति के बाद खड़गे के चेम्बर में मीटिंग होगी।

अपनी रणनीति पर नये ढंग से विचार करने के लिए संसद भवन परिसर में बैठक बुलाई है।

इंडिया गठबंधन के सूत्रों के अनुसार, बैठक बुधवार सुबह 09.45 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरेगे के चेम्बर में होगी, जिसमें गठबंधन के सदन के नेता संसद में सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

# पावर ब्रेकफास्ट के बाद मिले कर्नाटक में परिवर्तन के संकेत

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, पार्टी जो भी फैसला लेगी, हम उसे स्वीकार करेंगे

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को बेंगलुरु में अपने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (डीकेएस) से उनके बेंगलुरु-स्थित आवास पर 'पावर ब्रेकफास्ट' के लिए मुलाकात की। यह बैठक अन्य परिस्थितियों में देखी जाती तो सामान्य लग सकती थी।

इस विवाद का केन्द्र एक समझौता है, जो कथित तौर पर कांग्रेस की 2023 की चौकाने वाली चुनावी जीत के बाद हुआ था, कि सिद्धारमैया और डीकेएस पांच साल का कार्यकाल साझा करेंगे, यानी दोनों में से प्रत्येक मुख्यमंत्री के तौर पर ढाई साल काम करेंगे।

ये दोनों कांग्रेस नेता, जो 2023 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को

लेकर आपस में झगड़ रहे थे, नाश्ते पर मिले, जिसमें इडली, देसी चिकन करी और कॉफी (मुख्यमंत्री के लिए कम दूध वाली) के साथ दोनों ने चर्चा की। लेकिन इसका परिणाम अनिश्चित बना हुआ है, खासकर इसलिए कि सिद्धारमैया ने यह बताया कि दोनों ने आगामी कर्नाटक विधानसभा सत्र के बारे में बात की।

लेकिन सम्भवतः इस प्रकार की अपनी पहली स्वीकारोक्ति के रूप में, कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका समय समाप्त की ओर बढ़ रहा है, सिद्धारमैया ने यह भी संकेत दिया कि जब भी कांग्रेस के शीर्ष नेता उनसे कहेंगे, वे पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, "पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय

■ यह कह कर एक तरह से सिद्धारमैया ने भी पद छोड़ने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं।

■ अब जल्दी ही, संभवतया 8 दिसंबर को दोनों नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें भावी दिशा तय होगी।

■ सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी और खड़गे सत्ता परिवर्तन का प्लान तैयार करेंगे, पर, जैसी कि परम्परा है, अंतिम फैसला राहुल लेंगे और यह संभवतया डीके शिवकुमार के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि राहुल कार्यकाल के बीच में सत्ता परिवर्तन पर असहमति जाता चुके हैं।

■ सूत्रों का मत है कि डीके शिवकुमार व सिद्धारमैया दोनों ही बदलाव पर सहमत हैं, पर, तारीख पर सहमत नहीं हैं। जहाँ डीके शिवकुमार जल्द से जल्द बदलाव चाहते हैं, वहीं सिद्धारमैया इसे जितना संभव हो सके, टालना चाहते हैं, संभवतया कार्यकाल खत्म होने तक।

हम दोनों को स्वीकार होगा" सूत्रों ने कहा कि दोनों को दिल्ली बुलाए जाने की संभावना है, जहां वे 8

दिसंबर को उन नेताओं से मिल सकते हैं। योजना के अनुसार, सदन स्थगित हो जाने के बाद दोनों नेता बेलगावी (जहाँ

कर्नाटक विधानसभा स्थित है) से दिल्ली रवाना हो जायेंगे। सूत्रों ने समझाया कि यह यात्रा, जिसमें राज्य के